

उत्तराखण्ड शासन

आवास विभाग

संख्या- १५६/१/आ०-२००७-५१(आ०)/०७

देहरादून, दिनांक ०१ मई, २००७

आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या-CM-23/१/आ०-२००७-५१(आ०)/०७ दिनांक १६ अप्रैल, २००७ द्वारा उत्तराखण्ड नजूल नीति, २००५ की समीक्षा, राज्य के समग्र विकास हेतु डांचागत बुनियादी सुविधाओं के विकास तथा भू-माफियाओं की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिये शहरी आवास नीति एवं महायोजना में आवश्यक संशोधन पर विचार-विमर्श एवं अध्ययन हेतु प्रमुख सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में विभागीय समिति गठित की गयी थी। उक्त समिति के अध्यक्ष अब सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन होंगे।

उक्त के अतिरिक्त समिति का स्वरूप पूर्व की भांति ब्यथावत बना रहेगा।

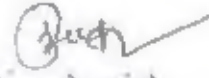
(गरिमा रौकली)
उप सचिव

संख्या १५६(१)/१ तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
२. उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।
३. निजी सचिव, सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन।
४. निजी सचिव, अपर सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन।
५. वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
६. सचिव, नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, नैनीताल।
७. सचिव, दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून।
८. निदेशक, एन०आई०सी० उत्तराखण्ड सचिवालय।
९. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(एस०के० पंत)
अनु सचिव